(ग) क्या यह भी सच है कि खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने बिना सरकार से स्वीकृति लिए विपणन विकास निगम पर कार्य आरम्भ कर दिया है और इस पर धनराशि खर्च की जा रही है ; और

(घ) यदि हां, तो इस कार्य को आरम्भ करने के क्या कारण हैं और ऐसे मामलों में सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम) :(क) से (घ) जी, हां। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने खादी तथा ग्रामोद्योग उत्पादों के लिए एक विपणन विकास निगम स्थापित करने के लिए एक प्रस्ताव भेजा था। योजना आयोग के साथ परामर्श करके इस प्रस्ताव की जांच की गई थी और की गई टिप्पणियों के आधार पर के०वी०आई० सी० ने प्रस्ताव की पुनः जांच करने और इसे सरकार के विचारार्थ प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था। तदनुसार, के०वी०आई०सी० ने इस विभाग को एक संशोधित प्रस्ताव भेजा था। इस प्रस्ताव की जांच की गई और के०वी०आई०सी० से इस विभाग को कुछ और जानकारी देने के लिए कहा गया है। इस बीच, के०वी० आई०सी० को निदेश दिया गया है कि सरकार की स्वीकृति मिलने तक प्रस्तावित निगम के गठन के बारे में कार्रवाई न करें। के०वी०आई०सी० ने सूचित किया है कि भारत सरकार की स्वीकृति के बिना विपणन विकास निगम का कार्य अभी शुरु नहीं हुआ है।

खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली के संबंध में ज्ञापन

3010. **श्री राम नरेश यादव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली तथा खादी तथा ग्रामीण उद्योग आयोग के बारे में कुछ पत्र, ज्ञापन आदि हाल ही में प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ; और

(ग) क्या सरकार ने आगे की कार्यवाही रोकने के लिए कोई अनुदेश दिये हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम):(क) से (ग) खादी ग्रामोद्योग भवनों सहित खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के बारे में सरकार को समय-समय पर अनेक अभ्यावेदन मिलते रहते हैं। जब भी ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं तो सरकार इन मामलों की जांच करती है और उचित कार्यवाही करती है।

किन्तु सरकार को अभी हाल ही में खादी ग्रामोद्योग भवन कर्मचारी संघ की ओर से दिनांक 29-1-93 का एक पत्र मिला है जिसमें खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के अधीन एक विपणन विकास निगम गठित नही करने का अनुरोध किया गया है। सरकार ने खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग को आदेश दिया है कि वह सरकार की पूर्वानुमति लिए बिना इस प्रकार का निगम गठित करने के बारे में आगे कोई कार्यवाही न करे।

Net profits of PSUs

3011. SHRI SUKOMAL SEN: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that net profits of the Central PSUs for 1991-92 have substantially increased over that of the preceding year;

(b) if so, the details of the companies making profits and those incurring losses; and

(c) the reasons for making profits by some companies and making losses by others?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT) WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY) (SHRIMATI KRISHNA SAHI): (a) Yes, Sir. The net profits of Central Public Enterprises have shown an increase of Rs. 202.60 crore from Rs. 2272.15 crores in 1990-91 to Rs. 2471.75 crores in 1991-92.

(b) The details of the companies making profits and those incurring losses have been indicated in statement 7A/7B of Vol. I of Public Enterprises Survey for 1991-92 placed in Parliament on 26.2.1993.

(c) The improvement/decline in profitability has to be reviewed against the back ground of multidimensional objectives of public Enterprises and the divergent and specific constraints faced by them. The general reasons for losses are locational disadvantages, very high initial capital investment, cost of learning and development and presence of a large number of Units taken over from the private sector, excess manpower etc.

Investments by NRIs

3012. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a large number of investment proposals from the Non-resident Indians have been cleared by the Foreign Investment Promotion Board, the SIA and the RBI;

(b) if so, the details of the projects approved for investments by the NRIs;

(c) how many investment proposals hove actually taken off the ground so far;

(d) the details of projects where no progress has been made so far;

(e) whether it is a fact that a large number of NRIs are backing out of these proposals;

(f) if so, the details thereof; and

(g) the action taken by Government to ensure that the NRIs bring their investments in India?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELPMENT) WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY) (SHRIMATI KRISHNA SAHI): (a) and (b) Yes, Sir. After the new liberalisation policy announced by the Government in July, 1991, proposals involving foreign investment, including NRI investment, to the extent of Rs. 66800 millions in different Sectors of Industries have been approved from August, 1991 to February, 1993.

(c) to (f) The gestation period of an industrial project varies from project to project, and industry to industry, as an entrepreneur has to take several effective steps for implementing project with foreign collaboration. Therefore, it is too early to assess the implementation of projects approved with foreign collaboration since August, 1991. State Governments follow up implementation of projects located in their States.

(g) NRIs and Overseas Corporate Bodies predominantly owned by them have been permitted to invest upto 100 per cent foreign equity in high priority and other industries with full benefits of repatriation of capital invested and income accruing thereon, subject to certain conditions. With a view to attract more NRIs/Foreign Investments, it has been decided to permit 100 per cent NRI investment on full repatriation basis in Export/Trading/Star Trading Houses at par with high priority industries.